SPECIAL MENTIONS

Arbitrary Stoppage of advertisements to small newspapers by DAVP

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, सरकार की ओर से प्रेस प्रचार प्रसार हेतु डी0ए0वी0पी0 एकमात्र जिम्मेदार संस्था है। अभी हाल में इस संस्थान ने मनमाने ढंग से 5000 समाचार पत्रों में से तीन हजार आठ सौ समाचार पत्रों को विज्ञापन आदि देने पर रोक लगा दी है। इस मनमाने ढंग से किए गए कृत्य से छोटे एवं मध्यम स्तर के समाचार पत्रों पर भारी संकट आ गया है। इन 3800 समाचार पत्रों पर विज्ञापन हेतु लगाई गई पाबंदी का कारण किसी नई विज्ञापन नीति का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उस तथाकथित नई विज्ञापन नीति के मापदंडों का कोई विवरण नहीं दिया गया है। जिन समाचार पत्रों को यह सजा दी गई है उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि प्रिन्ट ठीक नहीं है अथवा ले-आउट ठीक नहीं है या इसमें प्रकाशित सामग्री पर्याप्त स्तरीय नहीं है। श्रीमन्, इस फैसले से छोटे समाचार पत्रों पर भारी संकट आ गया है और इस प्रकार से बिना पर्याप्त कारणों के पाबंदी लगाया जाना देश के संविधान के खिलाफ है, बोलने-लिखने की स्वतंत्रता और बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन है। अत: श्रीमन्, सदन के माध्यम से सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस प्रकरण को स्वयं देखकर बुनियादी हकों पर डी0ए0वी0पी0 द्वारा किए जा रहे कुठाराघात को समाप्त करें।

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Sir, I associate myself with what Mr. Rama Shanker Kaushik has said. I also request the hon. Minister that if the National Advertising Policy has been adopted by the Government, it should be laid on the Table of the House.

Request to release additional grant for implementation of National Project for Cattle and Buffalo Breeding.

SHRIMATI VANGA GEETHA (Andhra Pradesh): Mr. Chairman, Sir, we are aware that the Government of India has launched a programme of restructuring of breeding operations to cover the entire breedable population through artificial insemination. For this, a project has been sanctioned to Andhra Pradesh. A self-implementing agency has been established to work independently, headed by a Director cadre officer of the Animal Husbandry Department, as Chief Executive Officer to monitor all the artificial insemination activities in the State. The Government of Andhra Pradesh has set a twin target of rapidly improving Dairy animals and enhancing process capacity simultaneously which is consistent with the Prime Minister's call for doubling of food production in ten years. The Chief Minister of Andhra Pradesh is regularly monitoring the progress of the scheme, which is being implemented by Andhra Pradesh Livestock Development Agency on monthly basis, because dairy development cannot progress without development of breeding infrastructure. To fulfil the requirement of the scheme, I request